

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): देश की 65 प्रतिशत आबादी से सीधे जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र आज भी देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसके बाद भी किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है। क्योंकि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य किसानों को प्राप्त ही नहीं होता। संपूर्ण लागत पर 20 प्रतिशत लाभान्श जोड़कर जो कीमत आती है वही लाभकारी मूल्य है और यही उत्पादों की लागत मूल्य की वास्तविक गणना ही अभी तक नहीं हो सकी है। देश में अभी जिस तरह से कृषि उत्पादों का मूल्य निकाला गया है वह अपर्याप्त और वास्तविक नहीं है। गत वर्ष सरकार ने विदेशों से 1650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जो किसानों को दिये जाने वाले समर्थन मूल्य से लगभग दोगुना है। देश की जनता को उचित मूल्य पर अनाज मिले यह जरूरी है लेकिन किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिले यह भी आवश्यक है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में किसानों को सीधे सब्सिडी देकर लागत मूल्य न्यूनतम कर दिया गया है जिससे वहां जनता को भी उचित मूल्य पर अनाज प्राप्त होता है।

मेरी सरकार से मांग है कि या तो सरकार वास्तविक लागत का निर्धारण कर उस पर लाभान्श जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित करे अथवा रासायनिक खाद कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को उनके बैंक खाते खोलकर प्रति एकड़ के मान से उनमें जमा की जाये ताकि कृषि लाभकारी हो और देश का अन्नदाता कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या न करे।